AN INSIGHT ANALYSIS OF INDIAN BUDGET 2018

DR VARINDER BHATIA[1]
PRINCIPAL SLBAWA DAVCOLLEGE BATALA PUNJAB

ABSTRACT

Indian finance bill 2018 has been stated to be pro poor and farmer . this research papers analyses in deep the different aspects of budget 2018 . It examines the logic behind supporting farm sector and also the betrayal of expectations of middle class in India.

वित्त मंत्री ने साल 2019 में होने वाले आम चुनावों से पहले मोदी सरकार का आख़ीरी पूर्ण बजट पेश किया है उम्मीद की जा रही थी कि यह बजट लोक-लुभावन होगा लेकिन उनका झुकाव किसानों और ग्रामीण इलाक़ों को राहत देने की तरफ़ अधिक था और इस में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि बदहाल कृषि क्षेत्र को समर्थन देना देश में आर्थिक और नैतिक ज़रूरत थी वेतनभोगी मध्यवर्ग को बजट से जिस तरह की उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुईं वैसे इस बजट को देश की वितीय हालत को ठीक करने वाला बताया जा सकता है। यह बजट भारत की अपग्रेडेड रेटिंग्स को सही ठहराता है। वित्त मंत्री ने 2018-19 के लिए वितीय घाटे को जीडीपी का 3.3 रखा है। इससे पहले फिस्कल डेफिसिट के 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया था

वित्त मंत्री ने भले ही स्वास्थ्य एवं कृषि क्षेत्र को जमकर सौगातें दी हों, लेकिन शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन करते समय उन्होंने संयम बरता । इस बजट में शिक्षा क्षेत्र में कुल 85010 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो पिछले साल के संशोधित बजट से मात्र 3141 करोड़ ही अधिक है। इस तरह देश के शिक्षा बजट में इस साल महज 3.69 फीसदी का ही इजाफा हुआ।

देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च से जुड़ी सुविधाओं को सुधारने के लिए वित्त मंत्री ने नए अभियान राइज (रिवाइटलाइजिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन) को शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत

[1] drbhatia.ppl@gmail.com

अगले चार साल में उच्च शिक्षा संस्थानों के सुविधाओं को सुधारने के लिए एक लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। ये निवेश हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (हीफा) के जरिए किया जाएगा।

तकनीकी के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलो स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देशभर से एक हजार बीटेक छात्र—छात्राओं को आईआईटी में रिसर्च के लिए चुना जाएगा और इन्हें सरकार आकर्षक फेलोशिप देगी। वहीं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बेहतर स्कूली शिक्षा के लिए वित्त मंत्री ने वर्ष 2022 तक 50 फीसदी आदिवासी जनसंख्या वाले ब्लॉक्स में एक एकलव्य स्कूल खोलने की घोषणा की है। ये स्कूल नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने आईआईटी और एनआईटी में 18 नए स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर खोलने की भी घोषणा की है।

२०१८ का बजट देश के शिक्षा क्षेत्र के लिए उत्साह वर्धक है इसमें शिक्षा के डिजिटल कारण के उपाय किये गए है वित्त मंत्री ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए आवंटन को दोगुना कर 3,073 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने 5 करोड़ ग्रामीण नागरिकों तक ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने के लिए 5 लाख वाई-फाई स्थलों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है।

इस बजट में सरकार द्वारा घोषित किए गए ज्यादातर खर्चे प्रॉडक्टिव इन्वेस्टमेंट हैं। अगर यह बजट सही से लागू किया गया तो आप इसके मीडियम और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखेंगे

बजट में गरीबों, किसानों और बुजुर्गों का काफी ख्याल रखा गया है वहीं, मिडिल क्लास की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। नौकरीपेशा लोगों को इस बजट में इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद थी, लेकिन इसमें कोई छूट नहीं दी गयी । सैलरीड क्लास के मौजूदा टैक्सेबल इनकम में से 40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है लेकिन इसका फायदा कम सैलरीवालों को ही मिलने की उम्मीद है

फ्लैगशिप हेल्थकेयर प्रोटेक्शन कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ परिवार को 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर मिलेगा यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से गरीब तबके के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा इससे हर भारतीय स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रेरित होगा

शिक्षा और हेल्थ पर एक फ़ीसदी सेस लगाने से टैक्स देने वालों पर अतिरिक्त भार पड़ जाएगा कॉरपोरेट टैक्स का दायरा व्यापक कर दिया गया है. इसके तहत जो कंपनियां पहले 25 करोड़ के टर्नओवर करती थीं अब इसमें 250 करोड़ तक के टर्नओवर पर भी 25 फ़ीसदी ही टैक्स लगेगा केंद्रीय बजट 2018-19 एकीकृत समाज सुधार पर केंद्रित है. कृषि, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, महिलाओं पर प्रस्ताव लागू होंगे तो इससे आय और लिंग भेद में मदद मिलेगी अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए धन के आवंटन को बढ़ाकर क्रमश: 56,619 करोड़ रुपये व 39,135 करोड़ रुपये किया गया है वित्त मंत्री ने महिलाकर्मियों को भी खुश करने के लिए कुछ वितीय उपाय भी किए है । सरकार सभी क्षेत्रों में आनेवाले वर्ष में 12 फीसदी ईपीएफ में निवेश करेगी। महिलाकर्मियों की ईपीएफ 12 फीसदी से घटाकर 8 फीसदी कर दिया गया है। इससे महिलाएं अधिक सैलरी घर लेकर जा सकेंगी संक्षेप में बजट २०१८ संतोष जनक है इसके आलोचनात्मक पहलुओं पर वित् मंत्री इस बात से तसल्ली ले सकते है की कुछ तो लोग कहेंगे

REFERENCES

1. **"Receipts" (PDF). Ministry of Finance, Government of India. Retrieved January 29, 2018.**
2. **"SUMMARY OF EXPENDITURE" (PDF). Ministry of Finance, Government of India. Retrieved January 29, 2018.**
3. **"Expenditure of Government of India" (PDF). Ministry of Finance, Government of India. Retrieved January 29, 2018.**
4. **"Debt and Deficit Statistics" (PDF). Ministry of Finance, Government of India. Retrieved January 29, 2018.**
5. **"Part V of the Constitution of India- The Union - Articles 110(a), 112, 113 and 114(3)" (PDF). Ministry of Law and Justice, Government of India. pp. 44–49. Retrieved January 30, 2018.**
6. **Khanna, Pretika; Varma, Gyan; Nair, Remya (January 5, 2018). "Union Budget 2018 to be presented on 1 February". Live Mint. New Delhi: HT Media Ltd. Retrieved February 16, 2018.**
7. **Taneja, Richa, ed. (January 29, 2018). "Budget 2018 To Be Presented By Finance Minister Arun Jaitley: Time, Date, All Details Here". NDTV. New Delhi. Retrieved January 30, 2018.**
8. **"Union Budget 2018 to be presented on February 1 - Times of India". The Times of India. New Delhi. TIMESOFINDIA.COM. January 5, 2018. OCLC 23379369. Retrieved February 16, 2018.**
9. **Seetharaman, G. (January 28, 2018). "Budget 2018: Here are the basics of this key annual event". The Economic Times. OCLC 61311680. Retrieved January 30, 2018.**